[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. पाम ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती से देश में नारियल उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याएं।

2. देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों से आम लोगों के सामने आ रही भिन्न-भिन्न समस्याएं।

अपराह्न 12.08 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूं:

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 30 अप्रैल, 2003 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

345 - 48

अपराह्न 12.09 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

भारत-पाक संबंध और हाल के घटनाक्रम के बारे में

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल की शाम को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री जमाली ने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की।

प्रधान मंत्री श्री जमाली ने श्रीनगर में मेरी टिप्पणी तथा भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में संसद के दोनों सदनों में दिए गए मेरे वक्तव्य की सराहना की और इसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की।

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7624/2003]

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करने के लिए हम किसी भी मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन हम एक सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर देते रहे हैं, जिसके लिए यह अत्यंत जरूरी है कि सीमा-पार से आतंकवाद को बंद करके इसके ढांचे का उन्मूलन किया जाये।

हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संबंध में मैंने आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग, आदान-प्रदान, दोनों देशवासियों के आपसी सम्पर्क तथा नागरिक उड्डन संबंधों के महत्व पर बल दिया। इनसे एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के जटिल मुद्दों का समाधान निकाला जा सकेगा। प्रधान मंत्री जमाली ने दोनों देशों के बीच खेल-खूद संबंध फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। हम इस बात पर सहमत हुए कि शुरुआती तौर पर, इन कदमों पर विचार किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाये तथा आदान-प्रदान के आधार पर नागरिक उड्डयन संबंधों को पुन: स्थापित किया जाये।

मैंने काठमांडू में सार्क सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में लिये गये निर्णयों पर व्यापक प्रगति के महत्व पर भी बल दिया है। काठमाण्डू में हुए समझौतों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सामान्य प्रक्रिया यह है कि हम इस प्रकार के वक्तव्य पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते हैं। हमारी सभा में प्रश्न पूछने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। पूरा देश चिन्तित है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता चला जा रहा है। पाकिस्तान उग्रवादियों को रासायनिक हथियार उपलब्ध करा रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तान से बात करने का क्या औचित्य है? ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, संसद ने इस मामले में एक संकल्प पारित किया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कार्यमंत्रणा समिति में आ सकते हैं और समय ले सकते हैं किंतु विशेष तौर पर मैं श्री शिवराज पाटील को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री को अपराह्न 12.30 बजे दूसरी सभा में जाना है। अत: बीच में टोकाटाकी करके कृपया अनावश्यक रूप से सभा का समय न लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री से क्वैश्चन पूछने की इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठिए। यदि हमारे पास समय हुआ तो आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

आप इस तरह का समय क्यों खराब कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): विपक्ष की नेता और कांग्रेस पार्टी यह कहती रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या को सुलझाने के लिए हमारे देश को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिये। यह कहते हुए मैं आपसे यह अनरोध करता हूं कि इस मुद्दे को सभा में विचारार्थ लिया जाए और सभी माननीय सदस्यों को दोनों पक्षों की सुविधानुसार बाद में अपना-अपना वक्तव्य देने की अनुमति भी दी जाये।

मुझे माननीय प्रधानमंत्री से एक या दो प्रश्न पूछने हैं और मुझे आशा है कि वे इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जनरल जे. गारनर ने कश्मीर मुद्दे पर एक वक्तव्य दिया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'एशियन ऐज' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं इस समाचार का एक भाग इस सभा में पढ़ने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं:

> ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हद से हद दिसम्बर 2004 तक चिरस्थायी कश्मीर समस्या का एक स्थायी समाधान निकल आए। अमरीकी सरकार ने इस समस्या को सदा के लिए सुलझाने का निर्णय लिया है। दक्षिण एशिया संसार का सबसे उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि यहां पर लोगों के पास व्यापक विध्वंस के हथियार हैं। अपने इतिहास के कारण यह उत्तर कोरिया से भी अधिक खतरनाक है। फिलीस्तीन मुद्दे को सुलझाने हेतु पश्चिमी एशिया में किए गए उपायों के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर समस्या को सुलझाया जाएगा।''

क्या सरकार ने इस समाचार को देखा है? क्या सरकार यह पता लगाएगी कि क्या ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया है और यदि यह सच है तो सरकार की इस वक्तव्य के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

हम माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे पर हमें कुछ बताएं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के संबंध में प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है, उसके बारे में सदन को लगातार विश्वास में लिया जाता रहेगा, किसी भी चीज पर पर्दा डालने का सरकार का इरादा नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा जोर इस बात पर दिया जायेगा कि क्या बातें हो रही हैं, उन सबका उद्घाटन किया जाए, तो मैं समझता हूं कि चर्चा में उससे सहायता नहीं मिलेगी। अगर सदन अलग चर्चा चाहता है, पूरे भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, समय निकालना अध्यक्ष महोदय आपकी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय: बिजनेस एडवायजरी कमेटी भी है।

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रधान मंत्री जी की इस बात को सदन स्वीकार करता है और अगले सप्ताह इस पर चर्चा की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: चर्चा के समय सदन में उपस्थिति भी अच्छी रहनी चाहिए, यह भी आपको विश्वास दिलाना होगा।

श्री पाटील साहब ने एक प्रश्न पूछा है, उन्होंने किसी जनरल साहब का एक बड़ा उद्धरण दिया है। मैंने भी वह उद्धरण देखा है। हमने उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण है। इस समय अनेक अटकलें चल रही हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो मध्यस्थता करना चाहते हैं। क्या मध्यस्थता करना चाहते हैं, क्यों मध्यस्थता करना चाहते हैं, इसके बारे में वे स्पष्ट नहीं हैं। भारत समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मामला है, वह एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे को आने की जरूरत नहीं है, न हम उसे स्वीकार करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी ने जब यहां कहा है कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी मान्य करेगी, फिर इस पर चर्चा होगी। अभी इस विषय में प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है। अभी श्री अरुण जेटली जी का एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, अभी वह करेंगे, उसके बाद जीरो आँवर लेंगे।

...(व्यवधान)